



वाँइस ऑफ

ओबीसी

सहयोग राशि रु. 20/-

अन्य पिछड़े की समसामयिक पत्रिका
अंक 20 - मार्च 2017

20 मार्च 2017: एक अविस्मरणीय दिन

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की भारतीय कैबिनेट ने दी मंजूरी



संसद की अन्य पिछड़े वर्ग की समिति ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा :
क्रिमी लेयर दायरा बढ़ाने की भी की गई मांग



NCBC एवं AIOBC पिछड़ा वर्ग महासंघ के अनवरत संघर्षों को मिली बड़ी सफलता

24 अगस्त 2016 को मुम्बई में एकत्रित सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संगठन की आमसभा आयोजित : नयी कार्यकारिणी का गठन



अखिल भारतीय यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ की मुम्बई में सभी प्रान्तीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 24 अगस्त 2016 को नयी कार्यकारिणी का गठन किया गया। नयी कार्यकारिणी की रिपोर्ट पृष्ठ 19 पर।



यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा वाराणसी में पाँच दिवसीय उत्सव का आयोजन

संगठन द्वारा यह कार्यक्रम लखनऊ, पटना, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, केरल, भूनेश्वर, जयपुर, उदयपुर आदि प्रमुख केन्द्रों पर भी आयोजित किया गया।



उदघाटन करते GM श्री लाल सिंह



उदघाटन करते DGM श्री केएस यादव



उदघाटन करते DGM श्री योगेन्द्र सिंह



उदघाटन करते Dy. ZM श्री गौतम पाठक



प्रतिभागी कार्यक्रम



वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की बैंक द्वारा आयोजित प्रोन्नति प्रक्रिया के अन्तर्गत अधीनस्थ संवर्ग से लिपिकीय संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग एवं अधिकारी संवर्ग में वरीष्ठ पदों के लिए प्रोन्नति से पूर्व यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा 5 दिवसीय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन बैंक के निर्देशानुसार किया गया।

प्रतिभागियों को संबोधित करते क्षेत्र महाप्रबंधक श्री लाल सिंह



वॉइस ऑफ ओबीसी

अन्य पिछड़े वर्गों की समसामयिक पत्रिका

अंक - 20, मार्च 2017

संपूर्ण संचालन अवैतनिक

(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)

संरक्षक

प्रो. एस्.एस्. कुशावाहा

परामर्श

जी. करुणानिधि, जे. पार्थसारथी

रवीन्द्र राम

प्रकाशक

रानी अमृतांशु

संपादक

अशोक आनंद

9415224153

मानद संपादक

अमृतांशु

9918306777

मानद सह संपादक

डा. हेमन्त कुमार

9453359701

विनोद प्रसाद शर्मा

9415889947

नवीन कुमार यादव

9415517017

प्रबंधक

अरविन्द कुमार

सहयोग

बसंत आर्य, सुनील कुमार, अशोक कुमार,

विजय कुमार, डी.डी. प्रसाद, उमेश कुमार

कुमार शशि, उपेन्द्र कुमार फाल, जयशंकर कुमार,

मो. जलानुद्दीन, ऋषिकान्त प्रसाद, दिलीप प्रसाद

बृज लाल, पंकज कुमार, अशोक यादव

पत्राचार

ई-मेल : aiobc.up@gmail.com

कठरा सं. 77, पी.सी.एफ. प्लाजा

नदेसर, वाराणसी-221002

इस अंक सहयोग राशि : 20 रुपये

डाक खर्च के साथ वार्षिक सहयोग 60/- डीडी/चेक
"Voice of OBC" के नाम वाराणसी में देय भेजें।

प्रकाशित रचनाओं से संपादन मंडल की
वैचारिक सहमति आवश्यक नहीं।

प्रकाशित लेखों संदर्भों के पुनर्प्रकाशन
से पूर्व अनुमति लें।

समस्त दाद विवादों का निपटारा वाराणसी न्यायालय में मान्य।

मुद्रक

प्रतीक प्रिंटर, वाराणसी। मो.: 9415623047

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्ति प्रदत्त

भारत सरकार ने दिनांक 20 मार्च 2017 को अन्य पिछड़े वर्गों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यह एक बड़ा फैसला है। लगभग 15 वर्षों से ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ बैंक वर्ड क्लासेज इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशनस ने NCBC Act 1993 में संवैधानिक संशोधन की मांग कर रहे थे। सरकार के इस आदेश से वर्तमान आयोग को समाप्त कर एक नए राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा जो विस्तृत शक्तियों से सम्पन्न होगा।

वस्तुतः वर्तमान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो स्वरूप था, वह भारतीय समाज के अन्तर्गत जातियों के सामाजिक आर्थिक स्तर के अध्ययन करने, उन्हें केन्द्र के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने अथवा सूची से बाहर करने संबंधित अपनी संस्तुति भारत सरकार को करने तक सीमित थी। इस आयोग के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिससे वह पिछड़े वर्गों के कार्मिकों अथवा सामान्य नागरिकों अथवा पिछड़े वर्ग से संबंधित सामाजिक संस्थाओं, संगठनों की शिकायतों को सुन सके। यह एक विडम्बना है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में असीम शक्तियां निहित हैं जिसमें शिकायतों को सुनने एवं दण्ड सुनाने की शक्तियां शामिल हैं किन्तु राष्ट्रीय आयोग को नहीं। वर्तमान फैसले से एक तरफ जहां नया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग शिकायतों को सुन सकेगा वहीं किसी भी स्तर के अधिकारी अथवा कार्यपालक को संबंधित शिकायतों की सुनवाई हेतु वह समनजारी कर सकेगा। जाहिर है भारत सरकार के आरक्षण संबंधी प्रावधानों की सही अनुपालना की जाच अब हो सकेगी एवं संबंधित दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कदम भी उठाए जा सकेंगे।

किन्तु यह संशोधन सामान्य नहीं है। प्रस्तुत आदेश को लागू करने के लिए सरकार को संसद में बिल पेश करना होगा। लोक सभा एवं राज्य सभा द्वारा बिल पारित करना होगा, इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत विधान सभाओं की इसे स्वीकृति भी लेनी होगी। तत्पश्चात संविधान के अनुच्छेद 338 में 338ब को जोड़कर संविधान को संशोधित किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 1990 एवं 2003 में संविधान के अनुच्छेद 338 एवं 338अ जोड़कर दो संविधान संशोधन किए गए जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित हैं। सरकार के फैसले के अनुसार संविधान संशोधन के पश्चात नया राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की तरह ही शक्ति सम्पन्न होगा।

भारत सरकार द्वारा यह फैसला ठीक उस वक्त लिया गया है जब भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव-17 में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। निसन्देह भारतीय जनता पार्टी ने यह महसूस किया कि इस ऐतिहासिक जीत में उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का बड़ा साथ प्राप्त हुआ है। यह एक स्वागत्य कदम है। साथ ही भारत सरकार से यह आग्रह है कि मौजूदा क्रिमी लेयर को स्पष्ट एवं पुर्न परिभाषित करें ताकि सभी राज्यों में इसकी एक रूपता बन सके और प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी एवं भारत सरकार के डीओपीटी (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एवं ट्रेनिंग) जैसी संस्थाएं इस संवेदनशील विषय पर पारदर्शी निर्णय ले सकें, और यह तभी सम्भव है जब क्रिमी लेयर संबंधी सरकार के निर्देश स्पष्ट हों। गौरतलब है कि मौजूदा प्रावधान में वेतन एवं कृषि से प्राप्त आय को क्रिमी लेयर की गणना में शामिल नहीं किए जाने का निर्देश है परन्तु सामान्य तौर पर अधिकारियों द्वारा इसकी अनदेखी की जाती है एवं वेतन को ही क्रिमी लेयर की सीलिंग मान लिया जाता है। अत एव हमारा आग्रह है कि भारत सरकार के OM - 36033/5/2004-Estt(Res) दिनांक 14.10.2004 का पुनराव लोकन एवं संशोधन की जाए। विदित हो कि अपने ताजा आदेश दिनांक 12.01.2017 को मद्रास हाईकोर्ट ने उक्त ओएम के पारा संख्या 9 पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं।



Signature

Blog : signpost2.blogspot.com
E-mail : aiobc.up@gmail.com

GANESH SINGH

Member of Parliament (Lok Sabha)

Chairperson

Joint Committee on Land Acquisition
Committee on Welfare of Other Backward Classes



सत्यमेव जयते

134, Parliament House Annexe,
New Delhi-110 001

Telephone: 011-23034144

Telefax: 011-23794033

E-mail: sganesh@sansad.nic.in
loksabhasatna@gmail.com

दिनांक : 20 मार्च, 2017

माननीय प्रधान मंत्री महोदय,

मैं स्वयं अपनी ओर से और संसद की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने अति व्यस्त दिनचर्या में से बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया। समाज के पिछड़े तबकों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करने का जो आपका संकल्प है, उससे हम सभी सदस्यगण भली-भांति परिचित हैं और इसी कारण देश के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के मन में आपसे असीम आशाएं भी हैं। संसद की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति भी समय-समय पर अपने प्रतिवेदनों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े मुद्दे भारत सरकार के समक्ष उठाती रही है। उनमें से कुछ प्रमुख बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिनपर सरकार से हमें सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा है।

I. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना

संसदीय समिति ने अपने विभिन्न प्रतिवेदनों में सरकार से इस बात की सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाय। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संविधान के अनुच्छेद 338 में और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद 338 क में स्थान दिया गया है। इसी तर्ज पर यदि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए भी एक नया अनुच्छेद 338 ख संविधान में जोड़ दिया जाय तो सरकार के इस कदम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सशक्त होगा।

II. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार क्षेत्र को विस्तार देना

विदित हो कि वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अधिकार क्षेत्र अत्यंत सीमित है जिसमें मुख्य रूप से कुछ जातियों और समूहों को पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने अथवा उक्त सूची से हटाने की अनुशंसा करना शामिल है। पिछड़े वर्गों से सम्बंधित अन्य समस्याओं पर विचार करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 338 (10) के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दिया गया है। अब जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को दो दशक से अधिक बीत चुके हैं, पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर विचार का अधिकार अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। सरकार इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 338 (10) में उपयुक्त संशोधन की पहल कर सकती है।

...२/

III. पिछड़े वर्गों के लिए बजट में अधिक धनराशि का प्रावधान करना

संसदीय समिति ने ऐसा पाया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को बजट में जो भी धनराशि मुहैया कराई जाती है, उसमें अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों सहित अन्य तबकों के लिए दी गई राशि का बटवारा करना होता है; फलस्वरूप अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से सम्बंधित कार्यक्रमों के लिए बहुत ही कम धनराशि मयस्सर हो पाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के बाद समिति के सभी सदस्यों का यह सर्वसम्मत मत है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत ही अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग विभाग बनाया जाए ताकि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग बजट का आवंटन हो सके। विकल्पतः सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत ही अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग उप योजना बजट की व्यवस्था की जा सकती है।

आशा है कि आप उपर्युक्त बिंदुओं पर कृपापूर्वक विचार करेंगे और सम्बंधित विभागों को यथोचित आदेश सम्प्रेषित कर हमें कृतार्थ करेंगे।

आदर सहित,

भवदीय,

(गणेश सिंह)

सभापति

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति

मार्टिनलूथर किंग

दिसम्बर 10, 1964, ओसलो नार्वे



विश्वाशांति के लिये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात् मार्टिनलूथर किंग ने अपने संबोधन में कहा कि मैं ऐसे वक्त में इस पुरस्कार को प्राप्त कर रहा हूँ जब अमेरिका के 22 मिलियन नीग्रो रंगभेदी अन्याय को खत्म करने के लिए दिनरात संरचनात्मक युद्ध में लिप्त हैं। मैं इस पुरस्कार को सिविल राईट्स मुवमेंट के लिए प्राप्त करता हूँ जिसने न्यायवादी व्यवस्था और स्वतंत्रता का राज्य कायम करने में अहम् भूमिका निभाई।...

..... मैं अवश्य यह पूछना चाहता हूँ कि यह पुरस्कार एक ऐसे आन्दोलन को क्यों प्रदान किया जा रहा है जो एक कठिन आन्दोलन के प्रति समर्पित रहा, जिस आन्दोलन ने शांति और भाईचारा नहीं जीता, जो कि इस पुरस्कार का अन्तस रहा है।

मैं इस पुरस्कार को प्राप्त करता हूँ क्योंकि मुझे अमेरिका में विश्वास है और मनुष्यत्व के अस्तित्व पर यकीन है।

..... यह विश्वास हमें सहारा दे सकता है ताकि हम भविष्य में अनिश्चितता का सामना कर सकें। यह विश्वास हमारे थके हुए भावों को नई ताकत देगा ताकि हम स्वतंत्रता के नगर की ओर निरन्तर आगे बढ़ सकें। यह जानते हुए कि हम एक सुन्दर सभ्यता के सृजन के संघर्ष के लिए पैदा हुए हैं। एक सुन्दर सभ्यता के जन्म के लिए किए जा रहे संरचनात्मक विद्रोह (Creative Turmoil) में जी रहे हैं।

- डॉ. हेमन्त कुशवाहा

GANESH SINGH
MEMBER OF PARLIAMENT (LOK SABHA)
CHAIRMAN
Committee on the Welfare of
Other Backward Classes



प्रकाशनार्थ

Office : 415, Parliament House Annexe,
New Delhi-110 001
Phone : 011-23034415, 23035197
Telefax : 011-23016807
Res. : 8, Gurudwara Rakabganj Road,
New Delhi-110 001
Phone : 011-23312604
Telefax : 011-23323644
E-mail : sganesh@sansad.nic.in
loksabhasatna@gmail.com

संसद की अन्य पिछड़े वर्ग की समिति ने प्रधानमंत्री जी को सौपा ज्ञापन

नई दिल्ली

आज 20 मार्च को संसद की अन्य पिछड़े वर्गों की स्थायी समिति के 18 सांसदों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को समिति के चेयरमैन श्री गणेश सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में समिति ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाये, तथा क्रीमीलेयर का दायरा बढ़ाया जाये एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह अत्यंत कम है। कुल बजट जो सामाजिक न्याय मंत्रालय को दिया जाता है उसमें से मात्र 21 प्रतिशत राशि दी जाती है उसे बढ़ाया जाये तथा वर्ष 2011 में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसमें अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या का प्रकाशन नहीं किया गया, तत्काल प्रकाशित किया जाये। पिछड़े वर्ग के जो बच्चे पिछले यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुये थे उनमें जिनके माता-पिता सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, बीमा क्षेत्र में नौकरी करते थे उनके वेतन के साथ कृषि आय को भी जोड़ दिया गया था जिससे वे आईएएस बनने से वंचित रह गये। इसलिये इसकी समतुल्यता निर्धारित की जाये तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये अलग मंत्रालय बनाया जाये।

सांसद श्री गणेश सिंह ने इन सभी बिन्दुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुये प्रधानमंत्री जी से मांग किया है कि उक्त सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुये पिछड़े वर्गों के साथ न्याय किया जाये।

अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित सदस्य— श्री गणेश सिंह, डॉ. स्वामी साक्षी जी महाराज, श्रीमती संतोष अहलावत, डॉ. बूरा नरसैय्या गौड़, श्री पी. करुणाकरन, श्री राजीव सातव, श्री रवीन्द्र कुशवाहा, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री नरेन्द्र बुदानिया, श्री रामनाथ ठाकुर, डॉ. विकास महात्मे, श्री रामनारायण डूडी, श्री हरिनारायण राजभर, श्री कंवर सिंह तंवर, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुण्डे, श्री रोडमल नागर, डॉ. बंशीलाल महतो, श्री राम मोहन नायडू, ज्ञापन सौपते समय उपस्थित थे।

“सादर”

भक्तप्रिय,

(गणेश सिंह)

Residence: Friends Colony, Near ITI, Satna, Madhya Pradesh-485 001
Phone: 07672-257999, Fax: 07672-257221

करीब एक छोटा
कि भारत का बहुर



वाराणसी | मंगलवार • 25 अक्टूबर • 2016

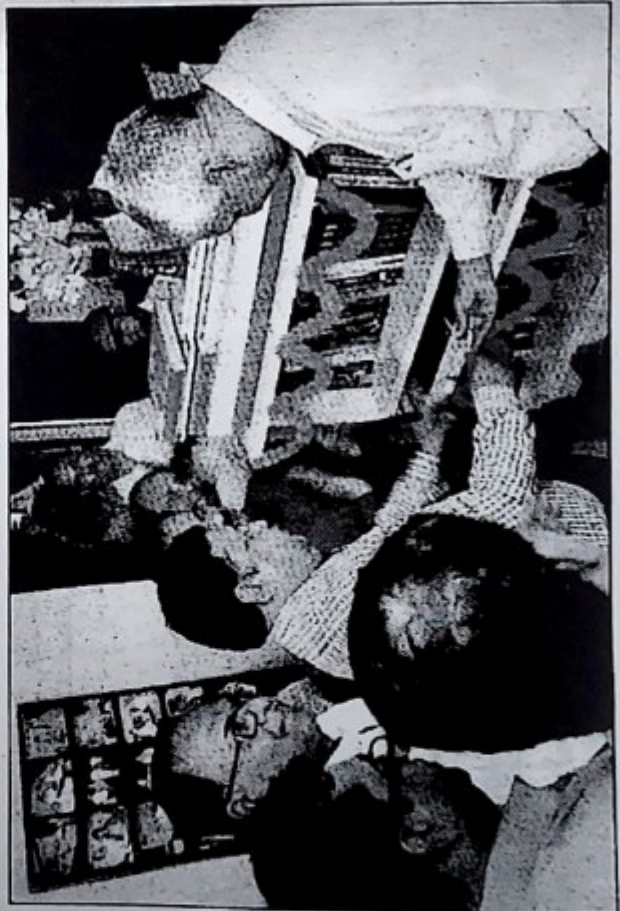
सहारा
www.rashtriyasahara.com |

स्वस्थ समाज का निर्माण करती हैं पुस्तकें

■ सहारा न्यूज ब्यूरो
वाराणसी |

नदेसर स्थित यूनिवर्सिटी बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ प्रांतीय कार्यालय में संगठन के पुस्तकालय का उद्घाटन यूनिवर्सिटी बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक लाल सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुस्तकें स्वस्थ समाज का निर्माण करती हैं। निश्चित रूप से इस पुस्तकालय से सभी सदस्य लाभान्वित होंगे। उन्होंने विवक्षित बताया कि संगठन समय-समय पर नवीनतम समाजिक पुस्तकों से पुस्तकालय को समृद्ध करते रहेंगे। इस अवसर पर नदेसर स्थित कर्मचारी कल्याण संघ प्रांतीय कार्यालय में पुस्तकालय का उद्घाटन

दिया-निर्देशों को प्रशिक्षण, सामाजिक न्याय पर केन्द्रीय पुस्तकें, समाज उत्थान एवं डा. भीम राव अम्बेडकर की जीवनी एवं संघर्ष से जुड़े साहित्य पर आयोजित पुस्तकें सहित सामान्य पुस्तकें सदस्यों के पढ़ने के लिए रखी गयी हैं। कार्यालय प्रतिदिन सांझकाल 7 बजे से 8 बजे तक खोला जाएगा। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी बैंक के क्षेत्र प्रमुख योगेश्वर सिंह, कर्ण सिंह खट्टर, गौतम पाठक, श्री. जलालुद्दीन, कुलकर्णी, अरुण कुमार, मुनील यादव, संजय कुमार, हरीश चामरा, संकर सामंत, पंकज सेठ आदि मौजूद थे।



The Pioneer

WEDNESDAY | OCTOBER 26, 2016

Library inaugurated

PIONEER NEWS SERVICE ■ VARANASI

Union Bank Backward Classes (OBC) Employees Welfare Association, UP has set up library at its state office in PCF Plaza, Nadesar here which was formally inaugurated by General Manager of the bank of Varanasi Region Lal Singh. Inaugurating the library Singh said that books builds healthy society and hoped that the members would take benefit of it. The general secretary of association Dr Amritanshu said that the objective behind to open the library was to enhance knowledge among members and appraised that the books

based on life of great personalities are available in library so as the members could take inspiration from them. The library will remain open between 7 and 8 pm daily. On the occasion many were present including regional head of bank Yogendra Singh, DGM Kapur Singh Yadav, sub zonal head Gautam Pathak and secretary of association Mo Jalaluddin.

KILLED: An old aged woman was lynched to death at her house in Jegular Koilabazar, under the Adampur police station on Tuesday. The police sent body for postmortem. The property dispute was said to be cause of the incident.



PARLIAMENT MATTER
MOST IMMEDIATE

No.41034/5/2014-Estt. (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
Establishment(Res.II) Section

North Block, New Delhi-110001
Dated the 20th October, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Data on the representation of Other Backward Classes in Central Government Services - Meeting taken by the Parliamentary Committee of Welfare of Other Backward Classes held on 14.10.2015.

The undersigned is directed to say that an online portal rrcps.nic.in already exists for uploading information on the representation of SCs, STs, OBCs and Persons with Disabilities. This information is obtained on annual basis as of 1st January of each year.

2. During the Sitting of the Parliamentary Committee of Welfare of Other Backward Classes held on 14.10.2015, Member Secretary of the National Commission for Backward Classes had pointed out to the Hon'ble Committee that in connection with formulation of a report on creamy layer, NCBC had requested all Departments/Ministries through Department of Personnel & Training to provide the information in a format prescribed by them, but the same was still awaited.

3. The Hon'ble Chairman and other Hon'ble Members of the Committee expressed dissatisfaction over low representation of OBCs in Central Government services and directed DoP&T to collect data sought by NCBC and submit to the Committee urgently.

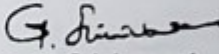
4. It is, therefore, requested that the data, in the enclosed format, relating to appointment of OBCs in the Ministries/ Departments be provided by 30.10.2015 (by mail and also by letter/fax) . The data should also be provided in respect of the attached and subordinate offices under their administrative control, in the enclosed format.

5. The Hon'ble Committee has indicated that delay in submission of the information would be taken seriously by them.

..2/-

6. In view of the directions of the Parliamentary Committee, the requisite information may be sent in this regard by 30.10.2015. If there are any genuine difficulties in providing the data within the prescribed time limit, the specific reasons for the delay and the likely date by which the same will be made available be informed to this Department.

7. This may please be treated as urgent.


(G. Srinivasan)

Deputy Secretary to the Government of India
Tele/Fax: 23093074.

Email: g.sreenivasan@nic.in

To

1. The Secretaries of all Ministries/Departments, as per standard list
2. Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat
3. Member Secretary, NCBC, R.K.Puram, New Delhi, for information.

 Copy also to Director, NIC for uploading the same on DoPT website

STATUS OF RECRUITMENT OF OBC CANDIDATES IN CENTRAL GOVERNMENT SERVICES IN MINISTRIES/DEPARTMENTS AND ITS ATTACHED AND SUBORDINATE OFFICES.

years	Groups	No. of posts reserved for OBC candidates	No. of posts filled in by OBC candidates	No. of posts carried forward
As on 1.01.2011	Group 'A'			
	Group 'B'			
	Group 'C'			
As on 1.01.2012	Group 'A'			
	Group 'B'			
	Group 'C'			
As on 1.01.2013	Group 'A'			
	Group 'B'			
	Group 'C'			
As on 1.01.2014	Group 'A'			
	Group 'B'			
	Group 'C'			
As on 1.01.2015	Group 'A'			
	Group 'B'			
	Group 'C'			

Most immediate

F. No.20/35/2015-Welfare
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

Jeevandeep Building, Parliament Street,
New Delhi, dated the 24 June, 2015

To

1. The Chairman & Managing Directors/MDs of All Public Sector Banks, MDS of SBI and it's Associate Banks / Public Financial Institutions and Public Sector General Insurance Companies.
2. The Chief General Manager (HRDD) RBI, Mumbai.
3. The Chairman, IBA/ IBPS.
4. Chairman PFRDA/IRDA.

Subject - Clarification sought by Banks in respect of OBC Candidates belonging to JAT community after Supreme Court's Judgments dated 17.03.2015.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Office Memorandum No. 36028/2/2012-Estt (Res.) dated 17.06.2015 from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training (DoPT), New Delhi, inter-alia addressed to the Department of Financial Services, on the subject mentioned above for information with the directions to ensure strict compliance to the instructions as contained in the enclosed O.M. in your respective organizations with the immediate effect.

2. Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

(Krishan Kumar)

Under Secretary of the Government of India
Tel. No. 23748736

Encl: As above.

Copy for information to:

1. JS (BA and P&I), JS (FI), JS (IF), Department of Financial Services.
2. CEO, Indian Bankers' Association, Mumbai
3. CEO, GIPSA, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi.
4. NIC Cell for placing on website of DFS.



No.36028/ 2 /2012-Estt. (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated the 17th June, 2015

OFFICE MEMORANDUM

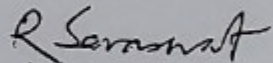
Subject: - Clarification sought by Banks in respect of OBC candidates belonging to JAT community after Supreme Court's judgment dated 17.3.2015.

The undersigned is directed to refer to D/o Financial Services' O.M No. 20/35/2015-Welfare, dated 11.6.2015 on the subject cited above and to say that the notification dated 4.3.2014 providing reservation for 'Jat' as OBCs in respect of nine States was issued by the M/o Social Justice & Empowerment which was quashed by the Hon'ble Supreme Court.

2. This issue had been examined in DoPT in the context of reservation for 'Jat' community in the Civil Services Examination conducted by UPSC. D/o Legal Affairs, when consulted opined that " the law is well settled that once the provisions of law have been declared unconstitutional and ultra vires, its effect would be as if the said provisions were never on the statute book. The declarations of provisions as ultra vires do not take effect from the date it is declared so but from the day of its inception. If the provision is unconstitutional and ultra vires and has been declared to be so by the Court, it was unconstitutional from the day it was enacted (Air 1994 Bom 261). This principle applies with equal force to the orders issued by the Govt. Since the Court has not saved the actions already taken, these actions will not survive because the order issued by the Govt. has been aside and quashed".

3. Based on Department of Legal Affairs' opinion, UPSC was requested to take further necessary action.

4. This issues with the approval of JS (AT&A).


(Raju Saraswat)
Under Secretary (Res-I)
Tel: 23092110

✓ Department of Financial Services
[Kind Attn: Shri Gulab Singh, Dy. Secretary (Welfare)]
3rd Floor Jeevan Deep Building, 10 Parliament Street
New Delhi.

THE CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-THIRD AMENDMENT) BILL, 2017: CONSTITUTIONAL POWERS TO NCBC

Bill 71 of 2017	Modi
<p>338B, Clause 3:</p> <p>After article 338A of the Constitution, the following article shall be inserted, namely:— "338B. (1) There shall be a Commission for the socially and educationally backward classes to be known as the National Commission for Backward Classes. (2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other Members and the conditions of service and tenure of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members so appointed shall be such as the President may by rule determine. (3) The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.</p>	<p>338B, Clause 3, sub-clause 2 shall be modified as follows:</p> <p>Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a Chairperson, retired Judge of Supreme Court or High Court, a Vice-Chairperson, Three Members out of which One Member is a Social Scientist and other two members with knowledge of the subject.</p> <p>Explanation:</p> <p>Supreme Court Judgement in Indra Sawhney Case forms the basis for constituting the National Commission for Backward Classes. The Judgement directs that there ought to be a permanent body in the nature of a Commission or Tribunal to which complaints of wrong inclusion or non inclusion of groups, classes and sections in the lists of Other Backward Classes can be made.....</p> <p>The body must be composed of experts in the field both of social and non-social and must be vested with the necessary powers to make a proper and effective inquiry.</p> <p>In the light of this NCBC act provided that the chairman should be a former judge so that the commission can adhere to a judicial approach; and member secretary should be a former secretary level officer of the government of India, one member should be a social scientist, And two persons with special knowledge of the socially backward classes. This feature of expert body, as directed by the Supreme Court, is not provided for in the composition of the NCBC Bill.</p> <p>The composition should retain this feature of an expert body as mandated by the SC and also developmental process expertise required by the developmental role.</p>
<p>338B, Clause 3. Sub-clause(5):</p> <p>It shall be the duty of the Commission—Sub-Clause: (c) to advise on the socio-economic development of the socially and educationally backward classes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;</p>	<p>338B, Clause(5) shall be modified as follows:</p> <p>It shall be the duty of the Commission—</p> <p>Sub-Clause: (c) to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the socially and educationally backward classes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;</p> <p>(Similar to provision in Article 338 (NCSC) & 338-A (NCST) relating to SC and ST commissions) sub clause (5) ©. That clause reads in both the cases of SC and ST as "to participate and advise on the planning process of socio – economic development of the Scheduled Castes".[Scheduled Tribes].</p>

Bill 71 of 2017	Modi
<p>338B, Clause 3, Sub-clause 9:</p> <p>The Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting socially and educationally backward classes.</p>	<p>338B, Clause 3, Sub-clause 9 to be removed.</p> <p>State Government should continue to have the powers to identify the SEBC.</p>
<p>338B, Clause 4:</p> <p>After article 342 of the Constitution, the following article shall be inserted, namely:—</p> <p>"342A. (1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public noti specify the socially and educationally backward classes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be socially and educationally backward classes in relation to that State or Union territory, as the case may be.</p> <p>342A(2) Parliament may by law include in or exclude from the Central List of socially and educationally backward classes speci in a noti issued under clause (1) any socially and educationally backward class, but save as aforesaid a noti cation issued under the said clause shall not be varied by any subsequent noti</p>	<p>338B, Clause 4:</p> <p>After article 342 of the Constitution, the following article shall be inserted, namely:—</p> <p>Article 342A (1) may be modi as follows:-</p> <p>"The President with respect to any State or Union Territory, and where it is a State, on the request made by the governor thereof, by public noti specify the socially and educationally backward classes which shall for the purposes of making provisions for reservation of posts under Government of India or under any other authority of government of India or under the control of the government of India or seats in the central govt educational institutions".</p> <p>Article 342A (2) may be modi as follows:-</p> <p>" President may, on the advise of the National Commission for Backward Classes include or exclude from the Central list of socially and educationally Backward Classes speci in a noti issued under clause (1)."</p> <p>Article 342A (3) may be added as follows:-</p> <p>"The Governor of a State, by public noti specify the socially and educationally backward classes which shall for the purposes of making provisions for reservation of posts under that State or under any other authority of the State or under the control of the State; or seats in the educational institutions within that State".</p> <p>Article 342A (4) shall be added as follows:-</p> <p>" The governor may, on the advice of the State Commission for Backward Classes include or exclude from the State list of socially and educationally Backward Classes speci in a noti issued under clause (3)."</p>





CONSTITUTION 123rd AMENDMENT BILL STATES LOSE RIGHTS

-Dr. Justice A.K. Rajan

On 16th August 1932, Prime Minister Ramsay Macdonald, gave the Communal Award, by which seats in the Indian Council were distributed among the various Religious and communal groups. Thus the Scheduled Castes were given the reservation in the Central Legislative Body. This was brought into force by The Government of India Act 1935. Therefore a list of Scheduled Castes was prepared. This list was included in the 195 Act as a Schedule. Thus the name Scheduled Castes was given to those castes included in that list. That list continues to be in force with very few inclusions, after The Constitution of India came in to force. Thus the Scheduled Castes were exhaustively counted and determined more than a century ago. Therefore there is no difficulty in identifying the people of the Scheduled Castes. The identification of SC and ST was complete as early as 1935.

2. But there was no such enumeration of the 'Backward Castes'. There is no exhaustive list of Backward Castes in any of the States. Further there are thousands of Backward Castes in India; and hundreds of backward castes in each State. Under Art 15(4) reservation cannot be made, for the Backward Castes. It can be made only for the citizens of "Socially and Educationally Backward Classes"[SEBC].

3. Since the Constitution of India did not define the term SEBC, and since there was great difficulty for such identification, The Supreme Court of India, in the MANDAL judgment, directed The Government of India to appoint a National Backward Classes Commission, for identifying SEBC for the purposes of appointment in the posts under the Government of India and in the other authorities of the GOI and in the 'Authorities Under the Control of GOI'.

4. The Supreme Court also directed that Each of the States in India, shall also appoint a 'State Backward Class Commission' for identifying the SEBCs in the States for the purposes of appointment in the posts under the State and in the posts of other authorities of the State or the authorities under the control of the States.

5. In view of the fact that such exercises of identification of the SEBC require a judicial decision, the Supreme Court also directed that the Chairman of such Commissions shall be a sitting or a retired Judge of the Supreme Court or High Court.

6. Further, a person belonging to any caste that is included in the Schedule is considered as a Scheduled Caste person in the whole of India. But, a person included in the list of SEBC prepared by one of the State Commissions for SEBC may not be included in the list maintained by the National Commission for Backward Classes and also by other State Commissions. Even within a State, in some cases, persons from some of the districts only are considered as SEBC.

7. Therefore, the act of inclusion or exclusion from the list of SEBC for the purposes of reservation in any State can be effectively done only by a State Backward Class Commission for extending any benefit of reservation within that State. That cannot be done by the NCBC. In Tamil Nadu within SEBC there is a sub classification as Most Backward classes [MBC]; in some other States SEBC is divided into four categories. Only because of that such a Scheme was framed by the Supreme Court. That is NCBC can identify the SEBC only for the purposes of Reservations made by the Government of India or under any other authority of GOI or authorities under the control of the GOI. In other words, NCBC cannot identify the SEBC for the benefit or Reservation given by any State or State Authority.

8. The NCSC or NCST has not made any sub classification within the SC or ST. In spite of the fact that some of the SC are very much backward vis a vis others. Tamil Nadu made a sub classification for Arunthathiyars (Madigas). That is now under challenge before the Supreme Court. Though there is a demand for making separate reservation for Madigas for many years in many States that could not be done by the National Commission.

9. When the NCBC was established it was noticed that the NCBC had no powers, except to include or exclude a classes within the SEBC. For effective enforcement it had to refer the matter to NCSC. Therefore there was a demand for conferment of similar Constitutional powers on the NCBC also. There was a demand to amend the constitution and to add a new provision similar to Article 338. But that was misunderstood by the Union Government.

10. The GOI introduced the 123rd Constitution Amendment, by which a new Article 338B was to be included. It reads identical with Article 338 (NCSC) and 338A (NCST), except sub clause (5) (c). That clause reads in both the cases of SC and ST as "to participate and advise on the planning process of socio – economic development of the Scheduled Castes". [Scheduled Tribes]. But in 338B (NCBC) the words used are "to advise on the socio-economic development of socially and educationally backward classes". **This appears to be a deliberate but a very vital omission.** Therefore, the powers of the proposed NCBC are not the same as that of NCSC or NCST.

11. Article 341 confers power on the President to specify the Scheduled Castes and Article 342 confers power on the President to specify the Scheduled Tribes. A similar provision 342A is proposed to be included

conferring powers on the President to specify the "**socially and educationally backward classes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be socially and educationally backward classes in relation to that State.....**". This provision may appear innocuous. But this provision, if comes into force, will cause irreparable damage to the cause of the SCBC and it will be detrimental to the cause of OBCs.

12. There is also an amendment to Article 366. A new sub clause 26(C) is added as follows:-

"(26C) "socially and educationally backward classes" means the backward classes as are deemed under article 342A for the purposes of this Constitution"

A combined reading articles 342A and 366(26C) would make it clear that after the 123rd amendment only the Union Government would have the power to determine if any class is a SEBC or not. The States will lose that power; that power vested with the States is taken away by the union Government. This is an affront on the federal structure of India. The States will become helpless to alleviate any redress to its own people even for any justifiable cause, even if there is an absolute necessity.

13. In the proposed Article 338B, Clause (2) provides as follows:-

"Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other Members and the conditions of service and tenure of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members so appointed shall be such as the President may by rule determine". The first part of this compound sentence mandates that a law is required for determining the structure of the Commission. That is, since the qualification for appointment of the Chairperson, Vice-Chairperson and other members are specified in this Article 338B, a law for that purpose is necessary. Such a law, The National Commission for Backward Classes Act 1993(Act 27 of 1993), under which a sitting or retired judge of the Supreme Court or High Court, as per the direction of the Supreme Court in the Mandal judgment, has been repealed by Bill No 70 of 2017. That Act need not have been repealed in its entirety; Chapter III, Powers and Functions of the Commission alone could have been repealed. Obviously the Union Government wants not to appoint a judge of the Supreme Court or High Court as the Chairperson. Such an appointment would be against the direction of the Supreme Court.

14. Article 342A takes away all the powers vested and were exercised by the States all along. If and when this article comes into force the States cannot declare or delete any SEBC from the list of OBCs in the States. That power can be exercised only by the Union Government. This article 342A(1) provides that "President may specify" the SEBC which shall **"for the purposes of this Constitution"** deemed to be SEBC in relation to that State. Instead Article 342A(1) may be modified as follows:-

"The President with respect to any State or Union Territory, and where it is a State, on the request made by the governor thereof, by public notification specify the socially and educationally backward classes which shall for the purposes of making provisions for reservation of posts under Government of India or under any other authority of government of India or under the control of the government of India or seats in the central govt educational institutions".

Article 342A (2) may be modified as follows:-

" President may, on the advise of the National Commission for Backward Classes include or exclude from the Central list of socially and educationally Backward Classes specified in a notification issued under clause (1)."

Article 342A (3) may be added as follows:-

"The Governor of a State, by public notification specify the socially and educationally backward classes which shall for the purposes of making provisions for reservation of posts under that State or under any other authority of the State or under the control of the State; or seats in the educational institutions within that State".

Article 342A(4) shall be added as follows:-

" The governor may, on the advise of the State Commission for Backward Classes include or exclude from the State list of socially and educationally Backward Classes specified in a notification issued under clause (3)."

15. Only such an amendment would be in consonance with the concept of federalism. It must be remembered that India is not a unitary country but a Union of States. Respecting the powers of the States is one of the important things which will go long way to improve the Unity and Integrity of India.

Conclusion:

16. The Constitution 123rd amendment Bill if becomes law of the land the States will be deprived of their power to declare any class as socially and educationally backward class in the State. The proposed amendment goes against the direction given by the Supreme Court in the Mandal Judgment. Article 342A, as proposed would be violating the concept of federalism. Unless the States are vigilant and protect their rights they would be stripped of their powers.

Chennai 16th April 2017.

[Justice A.K.Rajan]

Reproduced by : AIOBC Federation



AIOBC

e-mail: aiobc.gk@gmail.com
Mobile : 938 100 7998

**ALL INDIA FEDERATION OF OTHER BACKWARD CLASSES
EMPLOYEES' WELFARE ASSOCIATIONS**

H.O. : 139, Broadway, Chennai – 600 108.

Patron: **V.Narayanasamy (Hon'ble CM, Puducherry)**

President
V.Hanumantha Rao, Ex.M.P
Convenor, OBC MPs Forum

Working President
J.Parthasarathy
Editor, Voice of OBC

General Secretary
G.Karunanidhy
(Union Bank of India)

Treasurer
M.Elangovan
(IIT-Madras)

Vice Presidents

Asok Kr.Sarkar
(Reserve Bank of India)
V.N.Purushothaman
(NLC, Neyveli)
Ravindra Ram
(Bihar Federation)
U.Chinnaiah
(HAL, Hyderabad)
M.S.Rajarajan
(BHEL, Trichy)

Dy.Gen.Secretaries

V.Dana Karnachary
(Telengana State Fedn)
M.George Fernandez
(Bank of Baroda)

Organising Secretaries

Dr.Amritanshu
(UP State Federation)
G.Malles
(GIC-Oriental Insurance)

Secretaries

Pradeep Dhoble
(Air India, Mumbai)
K.Rajamohanadhas
(Indian Ordnance Factory)
R.Dharmaraj
(ICF, Chennai)
A.M.Muraidharan
(CPCL, Chennai)
R.K.Handique
(Assam State Federation)
R.K.Balamurugan
(Madras Fertilizers Ltd)
P.Srinivas Goud
(ECIL, Hyderabad)
M.Manicka Prabhu
(BDL, Hyderabad)
Niranjan Bhowmick
(RBI)
A.Kittusamy
(New India Assurance)
S.Pandu
(MIDHANI)
M.Maheswar Babu (BHEL,
Hyderabad)

Asst. Treasurer
Rajasekaran

Hon'ble
Thiru.**Narendra Modi**
Hon'ble Prime Minister
Govt. of India
New Delhi

Respected Sir,

CAT, Madras Bench judgement on Creamy layer

We submit to state that in a historic judgement dated 12.1.2017, CAT, Madras Bench headed by Hon'ble Justice A.Arumugaswamy and Hon'ble R.Ramanujam have directed the DoPT to withdraw the clarification in para 9 of the OM 36033/5/2004-Estt.(Res) dated 14.10.2004 to the extent it is made applicable to II-C and to reformulate it appropriately in the light of the observations made in the Judgement within a period of three months.

1. The case relates to non-allocation of service to two OBC applicants by wrong interpretation of creamy layer guidelines by DoPT in 2012. Both these candidates would have got the services in IFS and IPS as per their OBC status. But DoPT did not allocate service to them citing their parents salary income, who are working in PSUs.
2. The Judgement clearly states that OM dated 8.9.1993 brought out by DoPT based on 9 Judges Bench of Indra Sawhney v. Union of India and had been upheld by the Hon'ble Apex Court in Ashok Kumar Thakur vs. State of Bihar & Ors. (Reported in 1995(5) SCC 403).
3. The OM dated 8.9.1993 does not discriminate between salaried employees of Govt. and Public Sector /Private Sector employees and clearly states that income from Salary and Agriculture should not be taken into account for identifying creamy layer.
4. On the contrary, clear discrimination is brought about by paras 9 and 10 of the 'clarificatory' OM dated 14.10.2004, among the salaried class of Govt. employees vs. PSU/Private sector employees, which is certainly not inherent in the OM dated 8.9.1993, points out Judges.
5. The judgement states that "we are of the view that a needless and hostile discrimination has been introduced in the OM dated 14.10.2004 between Government servants and persons working in Public Undertakings and Private Sector in the manner of discrimination of their OBC/Creamy layer status and such discrimination is not based on any rational or intelligible differentia. Such discrimination does not flow from the OM dated 8.9.1993 and therefore, the contention that it has been upheld by the Hon'ble Apex Court in Ashok Kumar Thakur cited supra cannot validate the 'clarificatory' OM dated 14.10.2004."
6. Hence the Hon'ble Judges have directed DoPT to withdraw the

clarification in para 9 of the OM dated 14.10.2004 which is discriminatory and further directed DoPT to reallocate the service of two applicants on the basis of their OBC status within a period of three months from the date of this order (12.1.2017).

7. During the year 2016 also, some OBC candidates were denied service allocation by DoPT citing the same clarification in OM dated 14.10.2004 and still they have not given service allocation by DoPT.

In conclusion, we would like to state that, the OM dated 8.9.1993 specifies guidelines for application of creamy layer status to OBCs. It states that apart from Group A and B posts, for other categories in Government services, income should be taken but excluding salary income and agricultural income.

For Public sector employees, till their comparable post with Govt. department is identified, income should be taken but excluding salary income and agricultural income.

This is what the OM dated 8.9.1993 is all about.

But DoPT in the name of clarification issued a OM dated 14.10.2004, where they have interpreted in para 9 of the OM, that for public sector and private sector employees, their income includes Salary income. This is gross violation of the OM dated 8.9.1993.

The CAT, Madras Bench judgement clearly says that clarificatory OM cannot supercede the OM dated 8.9.1993 that has been upheld in Apex Court.

This discriminatory approach of DoPT has put lot of OBC candidates who have been successful in Civil Services Examination in non allocation of services, in the guise of creamy layer status. Even though, these candidates have produced valid OBC certificate and verified by UPSC, DoPT has ignored them citing para 9 of the clarificatory OM dated 14.10.2004.

Every year, few OBC candidates have been affected and the above candidates selected in 2012 could get justice only in 2017. How many of the other OBC candidates can move legally?

In 2016 also, lot of OBC candidates whose parents are working in PSUs, were denied service allocation by DoPT citing the same clarificatory OM dated 14.10.2004 and they are still waiting for service allocation.

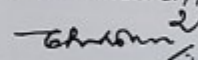
Sir, the representation of OBCs in Group A and B posts is less than 10% and in some of the Ministries, there representation is ZERO.

If this discriminatory approach is continued by DoPT, we can undoubtedly say that the representation of OBCs in Group A and B posts will not exceed 10% even after a century of implementation of 27% reservation to OBCs.

We therefore request you to kindly direct the DoPT not to take further legal steps but to withdraw the discriminatory clarification in para 9 of the OM dated 14.10.2004 and to allocate service to our OBC candidates based on their OBC certificate.

With respectful regards,

Yours sincerely,



(G.KARUNANIDHY)
GENERAL SECRETARY

अखिल भारतीय यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ की
28 अगस्त 2016 को मुम्बई में आयोजित आम सभा में नयी कार्यकारिणी चुनी गयी

क्रम	पद नाम	नाम	स्थान	सम्पर्क
1	अध्यक्ष	जी० करुणानिधि	चेन्नई	9381007998
2	कार्यकारी अध्यक्ष	रवीन्द्र राम	सेवा शाखा, पटना	9430829411
3	उपाध्यक्ष	रतनलाल सिरवी	शरदपुरा, राजस्थान	7665578222
4		नवीन कुमार	सेवा शाखा, लखनऊ	9415517017
5		विनोद प्रसाद शर्मा	कचहरी रोड, गाजीपुर	9918502055
6	महासचिव	जी० मलारकोडी	अन्ना नगर, चेन्नई	9444993844
7	संगठन सचिव	डॉ० अमृतांशु	अंचलीय कार्यालय, वाराणसी	9918306777
8	कोषाध्यक्ष	टी० रविकुमार	सेवा शाखा, चेन्नई	9940669385
9	सचिव	प्रकाश मजुमदार	कलकत्ता	8348833100
10		ए.आर.नरसिंह राव	IFB हैदराबाद	9701901717
11		विजय कुड़तरकर	CMS मुम्बई	9869414914
12		गोपीचंद परिहार	बेवार, राजस्थान	9414449555

केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य

क्रम	नाम	पदस्थी	क्षेत्र	सम्पर्क
1	पी० नागेश्वर राव	पट्टाभिपुरम् गुंटूर	विजयवाड़ा	9959311965
2	अली नवीन कुमार	हैदराबाद	हैदराबाद	9676630567
3	भारत भूषण	राजाबाजार	पटना	9939640135
4	अभय कुमार	मनेर	पटना	9431004842
5	रंजीत कुमार रंजन	समस्तीपुर मुख्य शाखा	समस्तीपुर	9430620740
6	पवन कुमार	एस.के. नगर, पटना	पटना	9835623573
7	सुशील कुमार	क्षे०का०, समस्तीपुर	समस्तीपुर	8578842323
8	राधेश्याम यादव	मायापुरी	नार्थ दिल्ली	9910739321
9	बी.एस.राजेश बाबू	अटीगल	त्रिवेन्द्रम	9447970435
10	एन. बाबू	मल्लेशवरम	बंगालुरु	9741787510
11	ब्रज किशोर परडिया	क्षे०का० भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	9078082288
12	पांडुरंग डी भंगाले	न्यू उसमानपुरा कॉलोनी	नासिक	9175888556
13	स्वाति भंगाले	नासिक सिटी	नासिक	8275053337
14	हिम्मत गोलमारे	सरल.पुणे	पुणे	9881060754
15	उदय डांगरे	यूएलपी, कादिवली	मुम्बई	9892373258
16	एस० नटराजन	तिरुवरूर	मदुरई	9789940100
17	पी० बालासुब्रमण्यम	क्षे०का० सेलम	सेलम	9787740125
18	एन० दुरई	वेल्लौर	सेलम	9843957530
19	जी० पलनी कुमार	कोचाडी	मदुरई	7598243463
20	पी० सतीश कुमार	नमावकल	सेलम	9655889637
21	एस० सत्यामुर्ति	कोलातूर	चेन्नई	9445172814
22	मो० जलालुद्दीन	चेतगंज	वाराणसी	9918301336
23	धर्मवीर सिंह	सेवा शाखा मेरठ	मेरठ	9412082765
24	अभिषेक सचान	क्षे० का० लखनऊ	लखनऊ	9918702015
25	राजीव रंजन	रौजा शाखा, गाजीपुर	गाजीपुर	9918501935
26	जितेन्द्र कुमार	मिलकीपुर	आजमगढ़	9532117625
27	लक्ष्मण सिंह संखला	बसनी	जोधपुर	9269309344
28	नौसद अली अंसारी	आर०ए०के०रोड शाखा	कलकत्ता	9836800645
29	सजल कुमार दत्ता	बालीगंज	कलकत्ता	9831848642
30	ज्योति वर्धन	डी०बी०पारा शाखा	सिलिगुड़ी	9775801032
31	जनम राय	गैटॉक	सिक्किम	9734902869

आम सभा का समापन संगठन सचिव डॉ. अमृतांशु के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ - अध्यक्ष



“सब मुझसे सहमत नहीं होंगे। पत्थर पर लकीर खींचने में नहीं आया। मैं केवल इतना करूँगा। अपना सच कहूँगा। वक्त को न्याय करने दूँगा।”

हर साल नई किताबें छपती हैं। हर साल नये पढ़ने वाले आते हैं। संस्कृति का यह ऐसा सातत्य है जो विद्या, विनय, मनुष्यता, संवेदना और विवेक को हर साल कुछ कदम आगे ले जाता है।

इतहास में अभागे

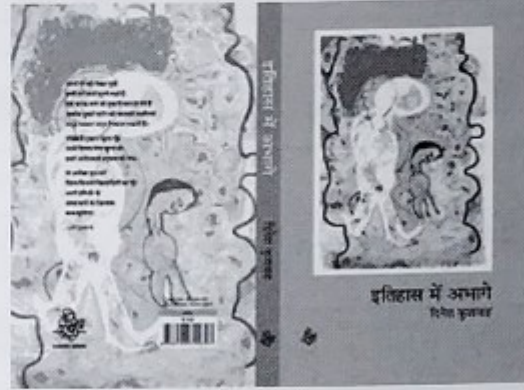
इतहास के नाम पर मुझे
सबसे पहले याद आते हैं
वे अभागे
जो बोलना जानते थे
जनिके खून से
लखा गया इतहास
जो श्रीमंतों के हाथियों के पैरों तले
कुचल दिए गए
जनिके चीत्कार में
डूब गया हाथियों का चघोड़ना

वे अभागे कहीं नहीं हैं इतहास में
जनिके पसीने से जोड़ी गयी
भव्य प्राचीरों की एक-एक ईंट
पर अभी भी हैं मसिर के परिमडि
चीन की दीवार और ताजमहल।

सारे महायुद्धों के आयुध
जनिकी हड्डियों से बने
वे अभागे
कहीं भी नहीं हैं इतहास में।

पुरातत्ववेत्ता जानते हैं
जनिकी पीठ पर बने
बकघिम पैलेस जैसे महल
वे अभागे भूत-प्रेत-जनिन
कुछ भी नहीं हुए इतहास के।

इतहास के नाम पर मुझे
याद आते हैं वे अभागे बच्चे
जो पाठशालाओं में पढ़ने गए
और इस जुरम में
टांग दिए गए भालों की नोक पर।



इतहास के नाम पर मुझे
याद आती हैं वे अभागी बच्चियां
जो राजे-रजवाड़ों के धायघरों में पाली गयीं
और जनिकी कोख को कूड़ेदान बना दिया गया।

इतहास के नाम पर मुझे
याद आती हैं वे अभागी
घसआरनि तरुणियां
जनिसे राजकुमारों ने कथिया प्रेम
और बाद में उनके सरि के बाल
कसि तालाब में संवार की भाँति तैरते मलि।

इतहास के नायकों का
भरण-पोषण करने वाले
इनके अभागे पति।ओं के नाम पर
नहीं रखा गया
हमारे देश का नाम भारतवर्ष।

हमारी बहुएँ और बेटियाँ
जनिहें अपनी पहली सुहागनि-रात
कसि राजा-सामंत
या मंदरि के पुजारी के
साथ बतानी पड़ी
इस धरती को उनके लएि
नहीं कहते भारत माता।

- विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग, ए.पी.एस. विश्वविद्यालय रीवा

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु संसदीय समिति
के अध्यक्ष श्री बिजोय कृष्णा हांडिक के निधन पर शोकसभा



Photos taken on the occasion of Condolence meeting to pay tributes to departed leader, six times Member of Parliament, former Union Coal Minister and former Chairman of Parliamentary Committee for OBC Mr.B.K.Handique (Assam)

The function was conducted on 6th August 2015 at Dy.Speaker Hall, Constitution Club, New Delhi by Mr.V.Hanumantha Rao, M.P., Convenor of Parliamentary Forum of OBC MPs.

Few other MPs Hukumdev Narayan Yadav, Devendra Goud, AshkTak Ali, Vishambhar Prasad Nishad, Smt. Kahkashan Perween attended the function.

-G.Karunanidhy
General Secretary

All India Federation of Backward Classes
Employees Associations.

साइमन कमीशन वापस जाओ

साइमन कमीशन भारत में ब्रिटिश हुकुमत द्वारा गठित वह आयोग था जिसे भारत में प्रजातांत्रिक मतदान पद्धति लागू करने से पूर्व भारतीय सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति के अध्ययन के लिए 30 मार्च 1927 को गठित किया गया था। यह रोमांचक सत्य है कि जिस वक्त भारत में बड़े पैमाने पर साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, ठीक उसी वक्त डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने अपने सभी दलित, शूद्र भाइयों को सूचित किया कि वे सभी स्थानों पर साइमन कमीशन का स्वागत करें। एक दुर्लभ पत्र जिसे कानपुर से झामलाल अहरेवाल ने लिखा था, आपके सम्मुख प्रस्तुत है-

**Welcome Simon or Parliamentary Commission on Morning
30th November, 1928 at Lucknow**

Our benign British Government has deputed a Parliamentary Commission to India which is touring in throughout the provinces and will reach at Lucknow on Morning 30th November, 1928.

We instruct our Achhut Shudra Community-being termed as Depressed Class, that if the community desires to have the full liberty, the rights and claims in the future constitution of India as gentlemen of Higher Classes have proposed and expressed their desirability of co-operation with the Simon Commission, the Achhut Community of U.P. must welcome the Commission with hope and certainty that the rights of 7 million of Achhuts will be sufficiently safeguarded thereby. In order to break legally the terrible laws of Manusmiriti and to break the chain of Slavery we appeal our Community to welcome the Commission and try your best to make the Simon Commission a great success.

JHAMLAL AHERWAR,

Proprietor : ADI HINDU SABHA

Proprietor : MONRO LEATHER MARKET

Phulgalli Anwarganj, Cawnpore

(सांभार : पुस्तक-पूना पैक्ट, क्यों, क्या और किसके लिए)



सम्राट प्रियदर्शी अशोक का विलक्षण व्यक्तित्व

इस वर्ष हम चैत्र शुक्ल अष्टमी यानी 5 अप्रैल 2017 को सम्राट अशोक का जन्म दिवस मना रहे हैं। सम्राट अशोक इस देश के ही नहीं, बल्कि विश्व के उन महानतम शासकों में से एक हैं जिनकी शासन प्रणाली आज भी अनुकरणीय है। अपने समय का महान योद्धा अशोक कलिंग युद्ध से अभिभूत होने के स्थान पर मर्माहत होकर किस प्रकार भगवान बुद्ध की शरण में जाता है, यह आज के शासकों के लिए उदाहरण है।

अशोक ने बौद्ध दर्शन पर आधारित एक ऐसी शासन व्यवस्था का कियान्वयन किया, जिसमें मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षियों, जीव-जन्तुओं, जल, जंगल, जमीन सबको बराबर महत्व दिया गया। अशोक ने पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़कर जिस संघवाद की स्थापना की, उसमें पूर्ण स्वायत्तता के साथ-साथ एक केन्द्रीय संप्रभुता की भी व्यवस्था थी। अशोक एक कुशल प्रशासक थे। मानवतावादी शासक थे। कलिंग के शिलालेख में उन्होंने प्रजा को पुत्र कहा और स्वयं को पिता। एक पिता की तरह ही वे अपनी प्रजा की भलाई सोचते थे। यही कारण है कि शिलालेखों में अशोक प्रियदर्शी अथवा देवानाम् प्रिय नामों का उल्लेख मिलता है।

अशोक का उद्देश्य धार्मिक सम्प्रदायों के बीच द्वेषभाव मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करना था। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने धर्म महापात्रों की नियुक्ति की। गुणी ब्राह्मणों एवं अन्य सम्प्रदाय के सन्यासियों को खुलकर दान दिए। जन कल्याण के लिए चिकित्सालयों, पाठशालाओं और सड़कों का निर्माण करवाया। धम्म प्रचार के लिए धर्मोपदेशकों की व्यवस्था की, धम्म यात्राओं का प्रबंध किया। साथ ही साथ राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करके शासन को चुस्त-दुरुस्त रखा।

अशोक का महत्व तो और भी बढ़ जाता है, जब हम देखते हैं कि उनके शासन के अनेक चिह्न आज भी हमारे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में अंगीकृत हैं। आज भी हम वैश्विक स्तर पर बौद्ध धर्म का विस्तार देख रहे हैं। निस्संदेह सम्राट अशोक का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। धम्म के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेन्द्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका तक भेजा था। इस प्रचार के प्रतीक स्वरूप बोधिवृक्ष की शाखा अपनी बेटों के हाथों भेजकर अनुराधापुरा में रोपण करवाया। इसके बावजूद सम्राट अशोक किसी अन्य धर्म के प्रति कही से भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे। उनके शासन काल में सभी धर्म-संप्रदायों के लोगों को सम्मानपूर्वक जीने की स्वतंत्रता थी। भगवान बुद्ध के समता-स्वतंत्रता एवं बन्धुत्व की भावना को सम्राट अशोक ने अपनी शासन-व्यवस्था में पूरी तरह क्रियान्वित किया था। उनके शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने प्रतिरोध के स्वर का गला कभी नहीं घोंटा। बल्कि, विभिन्न विचारधाराओं को फलने-फूलने का भरपूर अवसर प्रदान किया। इस तरह के विचार-विमर्श में वे स्वयं तथा उनके मंत्री भी हिस्सा लेते थे। निस्संदेह तेईस सौ वर्ष पूर्व जिस शासन-व्यवस्था को अशोक ने जन्म दिया था, वह आज के दौर को देखते हुए एक स्वप्न सरीखा लगता है।

डॉ. अम्बेडकर ने यथासंभव, यथासाध्य भारतीय संविधान को अशोक की शासन-व्यवस्था के अनुरूप रचने का प्रयास किया। इसकी पुष्टि संविधान की प्रस्तावना से तो होती ही है, उन तमाम प्रतीक चिह्नों में भी दिखाई देती है जिन्हें भारत सरकार ने अंगीकृत कर रखा है और जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ। वह चाहे राष्ट्रीय झण्डे का चक्र हो, चाहे भारतीय मुद्राओं पर अंकित सिंह शीर्षक।

यह हमारे देश का सौभाग्य है कि उसे अंबेडकर जैसे सपूत की प्राप्ति हुई। अंबेडकर ने अपने बारे में ठीक ही कहा था। यह देश उनके महत्त्व को उनके जाने के बाद स्वीकार करेगा। अपनी प्रतिभा के बल पर आज डा. अंबेडकर देश के ही नहीं, बल्कि विश्व के प्रथम पंक्ति के बौद्धिक विभूति के रूप में स्वीकृत हैं। उनके जन्म दिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व-ज्ञान दिवस घोषित कर हम भारतीयों का गौरव बढ़ाया है।

अशोक आनन्द

यूनियन बैंक अ.पि.व.क.कल्याण संघ, उ० प्र० के प्रान्तीय कार्यालय वाराणसी में बैंक के क्षेत्र
महाप्रबंधक श्रीलाल सिंह द्वारा संगठन के पुस्तकालय का उद्घाटन : 23 अक्टूबर 2016

पुस्तकालय का उद्घाटन यूनियन बैंक के वाराणसी क्षेत्र प्रमुख श्री योगेन्द्र सिंह, अंचलीय कार्यालय के उप महाप्रबंधक श्री कपूर सिंह यादव, उप अंचल प्रमुख श्री गौतम पाठक, सहायक महाप्रबंधक श्री धर्मपाल, राजभाषा मुख्य प्रबंधक श्री अरुण कृष्ण, संगठन के सचिव मो.जलालुद्दीन, आयकर विभाग के श्री पंकज कुमार, श्री महेन्द्र नाथ एवं बैंक के तमाम मित्रों सहित सम्यक समाज के श्री वीरेन्द्र मौर्य एवं सदस्यों की उपस्थिति में महाप्रबंधक श्री लाल सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री डॉ. अमृतांशु ने प्रस्तुत किया।



बचत खाते से जोड़ें आधार खोलिए खुशियों के नए द्वार

निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम का उपयोग करके अपने आधार नंबर को अपने यूनियन बैंक अकाउंट से जोड़िए:

- एसएमएस करें यूआईडी <स्पेस> 15 अंक बचत बैंक खाता नंबर <स्पेस> 12 अंक आधार नंबर और भेज दें 922 300 8486 पर
- किसी भी यूनियन बैंक एटीएम पर अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करें, पिन एंटर करें और विकल्प आधार पंजीकरण चुनें.
- www.unionbankofindia.co.in पर विजिट करें और अपने आधार नंबर जोड़ें विकल्प पर क्लिक करें
- अपना मूल आधार कार्ड लेकर किसी भी यूनियन बैंक शाखा में जाएँ

गौरवशाली सहभागी:



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **Union Bank of India**
अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India



हेल्पलाइन नं.: 1800 208 2244 / 1800 22 2244 (टोल फ्री नं.) | 080 2530 0175 (सशुल्क) | +91 80 2530 2510 (एनआरआई के लिए)
www.unionbankofindia.co.in हमें फॉलो करें [f @unionbankofficial](https://www.facebook.com/unionbankofficial) [t @UnionBankTwain](https://twitter.com/UnionBankTwain)